

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़

पीएससी अधिकारी-हरिसिंह गीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या - डिक्री 80 सन् 2019

पंजीयन दिनांक 11.07.2019

1. राजू पिता नन्दा जाति गुर्जर निवासी रेन का खेडा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़
2. गोविन्द पिता नन्दा जाति गुर्जर निवासी रेन का खेडा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़
3. श्रीमती सरदार बाई पुत्री नन्दा जाति गुर्जर निवासी रेन का खेडा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़
- श्रीमती नन्दु बाई पत्नि मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी रेन का खेडा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़



-अपीलांतगण

विरुद्ध

1. बाला पिता भेरा जाति गुर्जर निवासी रेन का खेडा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़
 2. मदन पिता भेरा जाति गुर्जर निवासी रेन का खेडा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़
 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़
- रेस्पोंडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध
अंतिम निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा
प्रकरण संख्या 30/2013 अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2018

- उपस्थित वक्त बहस -
1. छोगालाल जाट-अधिवक्ता अपीलान्तगण
 2. खुमराज कुमावत-रेस्पोंडेन्ट सं. 1
 3. पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट सं.3

निर्णय

दिनांक 30.09.2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोंडेन्ट सं. 1 वादी की ओर से अपीलान्त व अन्य रेस्पोंडेन्टगण के विरुद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया कि मोजा रेन का खेडा तहसील रावतभाटा की खाता सं. 181 में दर्ज आराजी नम्बर 483,484,535,536,539,630,734,827 कुल किता 8 रकबा 3.29 हैक्टेयर के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया। वादपत्र में अंकित किया कि उक्त आराजीयात अपीलान्तगण व रेस्पोंडेन्ट सं. 1 व 2 के शामिल की खातेदारी की है। रेस्पोंडेन्ट सं. 1 वादी अपीलान्तगण व रेस्पोंडेन्ट सं. 2 पारिवारिक बंटवाड़े अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजीयात में रेस्पोंडेन्ट सं. 1 वादी का 1/4 व शेष हक व हिस्सा अन्य प्रतिवादीगण अपीलान्तगण व रेस्पोंडेन्ट सं. 2 का निहित है। उसी अनुसार

राजस्थान अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात का बंटवाडा कराया जाकर राजस्व रेकार्ड मे अलग-अलग दर्ज करवाई जावे।

उक्त आशय का वादपत्र रेस्पोजेन्ट सं. 1 वादी की ओर से अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलान्दगण व रेस्पोजेन्ट सं. 2 व 3 प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर अपीलान्दगण व रेस्पोजेन्ट सं. 2 व 3 की तामील हुए बगैर एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर राजस्व लोक अदालत मे नियत किया जाकर बिना अपीलान्द प्रतिवादीगण को सुने व बिना किसी लिखित राजीनामे के दिनांक 12.04.2014 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे अपीलान्दगण प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति मे बिना सूचना दिये फर्द बंटवाडा तैयार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। उक्त फर्द बंटवाडे पर आपत्ति व एतराज सुने बगैर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलान्दगण प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की गई जो इस न्यायालय द्वारा पंजीबद्ध की जाकर रेस्पोजेन्टगण वादी व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोजेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपीलान्द प्रतिवादीगण ने इस न्यायालय मे म्याद बाहर अपील प्रस्तुत की। म्याद को कन्डोन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मय शपथ पत्र कानून म्याद अधिनियम 1963 प्रस्तुत किये। अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट सं. 1 ने प्रार्थना पत्र आ जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम की बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्द प्रतिवादी सं. 1 से 4 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोजेन्ट सं. 1 वादी ने सहखातेदारी की कृषि आराजीयात के बंटवाडे का वादपत्र प्रस्तुत किये व यह तथ्य अंकित किये कि उक्त वादपत्र मे रेस्पोजेन्ट सं. 1 वादी का 1/4 हक निहित है। उसी अनुसार विवादित कृषि आराजीयात का बंटवाडा कराया जावे। उक्त पत्रावली दिनांक 10.06.2013 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलान्दगण व रेस्पोजेन्ट सं. 1 से 4 प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। पत्रावली मे अपीलान्द सं. 1 व 2 को कोई सम्मन तामील होकर अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नही हुआ। फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अपीलान्द सं. 1 व 2 का सम्मन नोटिस तामील होना मानते हुए दिनांक 05.08.2013 को एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रतिवादी सं. 3 का सम्मन जो कि बड़तजार था। उक्त

पत्रावली को दिनांक 12.04.2014 को लोक अदालत में नियत की जाकर बिना किसी लिखित राजीनामे के प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है। तहसीलदार रावतभाटा को फर्द बंटवाड़े हेतु कमिश्नर नियुक्त किया। कमिश्नर स्वयं द्वारा फर्द बंटवाड़ा तैयार नहीं किया जाकर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से बिना पक्षकारान को सूचित किये तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अपीलान्दगण प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 की आपत्ति व एतराज को सुने बगैर अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय में अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है। अपनी बहस के समर्थन में आरआरटी 2022 पार्ट-1 पेज 61 व आरआरटी 2021 पार्ट-1 पेज 469 प्रस्तुत की। अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।



अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट सं. 1 वादी ने अपनी बहस में अंकित किया कि विवादित कृषि आराजीयात रेस्पोंडेन्ट सं. 1 वादी रेस्पोंडेन्ट सं. 2 व अपीलान्दगण के संयुक्त खातेदारी की अपेक्षा विभाजन कर अलग-अलग काबिज होकर उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे अनुसार विवादित कृषि आराजीयात का विभाजन किये जाने हेतु अधीनस्थ विचारण न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत किया जाकर बंटवाड़ा चाहा जिस पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय में वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये जो प्रोपर तामील होकर प्राप्त हुए जो अधीनस्थ विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। फिर भी अपीलान्दगण प्रतिवादीगण अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए जिससे अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय ने अपीलान्दगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रकरण को लोक अदालत में नियत किया जाकर बंटवाड़े का वादपत्र होने से प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना में कमिश्नर स्वयं के द्वारा फर्द बंटवाड़ा तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। फर्द बंटवाड़े में सभी को अपने हक व हिस्से के अनुसार रकबा दिया गया है। उक्त फर्द बंटवाड़े को मध्यनजर रखते हुए अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय ने अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है। अपीलान्दगण प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 रेस्पोंडेन्ट सं. 1 वादी से छेड़पता रखते हैं। बंटवाड़ा नहीं होना देना चाहते हैं जिससे गलत तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट सं. 3 ने अपनी बहस में अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत होना बताते हुए अपीलान्दगण प्रतिवादी सं. 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय में रेस्पोंडेन्ट सं. 1 वादी की ओर से अपीलान्दगण व रेस्पोंडेन्ट सं. 2 व 3 प्रतिवादीगण के विरुद्ध बंटवाड़ा स्थायी निषेधाज्ञा वादपत्र प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पंजीबद्ध किया जाकर सम्मन नोटिस जारी किये गये। दिनांक 12.04.2014 को राजस्व लोक अदालत के तहत प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई व उसके पश्चात् दिनांक 10.07.2014 को संशोधित प्राथमिक निर्णय व डिक्री अपीलान्दगण


प्रतिवादी सं. 1 से 3 की अनुपस्थिति में पारित की गई। तत्पश्चात् कमिश्नर तहसीलदार रावतभाटा को फर्द बंटवाड़ा प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। पत्रावली में संलग्न फर्द बंटवाड़ा दिनांक 20.04.2018 जो कि पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार किया जाना पाया जाता है। उक्त फर्द बंटवाड़ा अधीनस्थ अधिकारियों से लिया जाकर कमिश्नर तहसीलदार रावतभाटा के द्वार विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त फर्द बंटवाड़े में अपीलान्दगण प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 को सूचित किया जाना कही अंकित नहीं किया गया है। जबकि राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के बंटवाड़े नियम 18 से 21 के अनुसार कमिश्नर स्वयं के द्वारा उभयपक्षों को सूचित किया जाकर उभयपक्षों की उपस्थिति में फर्द बंटवाड़ा तैयार किया जाना प्रतिपादित किया गया है। जिससे अपीलान्द की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2021 पार्ट-1 पेज 469 व आरआरटी 2022 पार्ट-1 पेज 61 इस प्रकरण में चर्चा होने से अपीलान्दगण प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्दगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा प्रकरण संख्या 30/2012 अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2018 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्षकारान की उपस्थिति में फर्द बंटवाड़ा, बंटवाड़ा नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करें व उक्त फर्द बंटवाड़े पर उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अजसरे नवनिर्णय पारित करें। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में दिनांक 14.11.2022 को सुनवाई हेतु स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।




 (हरिसिंह मीना)
 राजस्थान अपील प्राधिकारी
 चित्तौड़गढ़ (राज.)
 चित्तौड़गढ़(राज0)